They were remanded to Customs custody upto 29-10-1977 They have since been detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act on 29-10-1977

12.22 hrs

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRIMATI INDIRA GANDHI AND OTHERS—contd

MR SPEAKER In view of the appeal by the two Ministers, are you reconsidering your position, Mr. Gauri Shankar Rai?

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के एजेण्डा पेपर में मेरा प्रस्ताव नहीं है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति अत्यन्त आदर रखते हुए भी बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 226 के अन्तर्गत दूसरा मोशन पेश किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। यह न केवल नियम 226 में ऐसी व्यवस्था है बल्कि इस सदन में ऐसी परम्परा भी रही है कि दूसरा सबस्टेंटिव मोशन पेश किया जा सकता है। 5 अप्रैल, 1970 को डा० लोहिया ने, स्वेल्लाना के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने डा० राममुहाग सिंह को वैकल्पिक प्रस्ताव रखने की अनुमति दी थी। इसलिए जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि विशिष्ट सबस्टेंटिव रिजोल्यूशन में इसका संशोधन हो ही नहीं सकता, यह हो सकता है और स्पीकर की भी ऐसी व्यवस्था है। यह उस समय की बड़ी लम्बी प्रोसीडिंग है, अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो मैं इसे पढ़ दूं ?

MR SPEAKER: You can be brief. I have read the proceedings.

श्री गौरी शंकर राय : इसके बाद परम्परा के लिहाज से मैं कहता हूं कि जो मोशन मैंने पेश किया उस पर उसके बाद आपत्ति उठाई गई और उस पर बहस हुई। मैं समझता हूं कि उस आपत्ति के बावजूद भी मेरे उस मोशन को एजेंडा पर आना चाहिए था। जिस बात पर विवाद होता है वह एजेंडे पर न रखी जाए यह ठीक नहीं है।

MR SPEAKER You are not correct It is in the agenda Please see the agenda It reads

"ALSO further consideration of amendments (printed on separate list) moved on the 17th November, 1977

It is there Would you like to say anything else?

श्री गौरी शंकर राय : कार्रवाई जो होती है उसको तो आप हटा नहीं सकते हैं। उस को एजेंडे पर हमारे सामने आना चाहिए था।

मेरा खयाल है कि आपका दिमाग स्पष्ट हो गया होगा। इतने सीनियर मेम्बर्ज के होने के बाद भी और आप जैसे अनुभवी न्यायाधीश के यहां रहने के बाद भी मैं यह समझता हूं कि रूल 226 स्पष्ट है, उस में दो मोशंज की व्यवस्था है, वैकल्पिक मोशंज की व्यवस्था है। आप कल्पना करें कि लिमये जी का प्रस्ताव पास नहीं होता है तो मेरा यह कटेशन है मेरा जो प्रस्ताव है उसको आप पास करिये। इस वास्ते अलग से एक प्रस्ताव की आवश्यकता को मैं महसूस करता था। अगर इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प हो सकता है तो उसके बारे में मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूं। आप सदन को गाइडेंस दें। अगर वैकल्पिक प्रस्ताव सदन में पास होना है तो

वह बिना सबस्टैंटिव मोशन के कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप प्रकाश डालें। रूलिंग भी इसके बारे में स्पष्ट है। बिना एक निश्चित प्रस्ताव के वैकल्पिक प्रस्ताव हो नहीं सकता है। जो रूल है वह निश्चित रूप से प्रिसाइज है। दो प्रकार के प्रस्तावों की व्यवस्था उस में जनबूझ कर की गई है, अनजाने में नही की गई है। मैं चाहता था कि वह एजंडे पर आता। डा० लोहिया के केस में जो रूलिंग हुआ है उसको मैं पढ़ देता हूं :

I am now reading out the proceedings in question:

"Mr. Speaker: Dr. Ram Manohar Lohia moved his motion to refer the question of privilege to the Committee of Privilege, Dr. Ram Subhag Singh moved another motion to the effect that the House is of the opinion that no breach of privilege or contempt of the House has been committed by the Minister concerned.

A point of order was raised that this motion moved by Dr.Ram Subhag Singh was out of order as it was in the nature of an amendment to the original motion of Dr. Ram Manohar Lohia, and under rule 344(1) an amendment has to be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

I have heard all the points of view, both for and against this point of order. I am of opinion that rule 226 is a self-contained rule. So far as the motions relating to the question of privilege are concerned. Rule 226 reads as follows:

"If leave under rule 225 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to a Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privillage or by any other member."

This rule envisages that either one of the two motions can be made under this rule. The original motion of Dr. Ram Manohar Lohia states that a *prima facie* case of breach of privilege has been made out and the matter should be referred to the Committee of Privileges for investigation. If this motion is voted down, it only means that the matter is not referred to the Committee of Privileges, and the substantive part of the question of privilege namely whether a breach of privilege or contempt of the House has been committed remains, and the House has to give a decision on the merits of the case.

Therefore, Dr. Ram Subhag Singh is within his right to invite the House to come to a decision whether any breach of privilege or contempt of the House has been committed.

I rule that both the motions are in order and they should be put to the vote of House one after the other First, Dr. Ram Manohar Lohia's motion will be put to the vote of the House, and if it is not carried, then Dr. Ram Subhag Singh's motion will be put to the vote of the House."

मैंने जल्दी में अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया है। यह प्रस्ताव क्या है और क्यों किया गया है यह मैं बताना चाहता हूं। यह कंटैम्प्ट आफ दी हाउस का प्रस्ताव है। सदन ने और आपने उसको मान्यता दे दी है। दो प्रस्ताव मैंने रखे हैं। एक यह रखा है कि इतनी एवीडेंस हमारे सामने हैं कि उस में और ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाउस सैटिसफाईड हो तो वह एक्शन ले सकता है। कुछ मित्रों ने कहा है कि उनको जेल कर देना चाहिए ऐसा मैंने क्यों लिखा ? इसलिए लिखा कि इससे अधिक लिखने की हैसियत नहीं है इस हाउस की। फांसी तो लिख नहीं सकता था। जिन मित्रों ने मुझ से रिक्वेस्ट की है, बावजूद इसके कि प्रजातन्त्र एक गेम आफ़ परसुएशन है,

मैं कहना चाहता हू कि मैं उनसे मजबूती से डिफर करता हू । यह सदन हायेस्ट कोर्ट आफ दी लैंड है और इधर बैठने वाले मित्र पीपुल्स कोर्ट मे विश्वास करते हैं, और वह यही हाउस है । किसी को भी सजा देने के लिए यह सदन सक्षम है । मान्यवर, दो तरह के क्रिमिनल्स होते है । एक हैबिचुअल होते हैं जिसके बारे मे ज्यादा ऐवीडेंस की जरूरत नही है । और ऐवीडेंस स्पष्ट है जिस पर ज्यादा इस हाउस को विचार करने की जरूरत नही है (व्यवधान) मान्यवर कभी-कभी दुनिया के इतिहास मे ऐसे समय आये है जब कानून की सीमा अपराधी को दड देने मे असमर्थ रही है । अपराधी का अपराध दडाधिकार की सीमा के बाहर होता है । आपको याद होगा कि हिटलर के जमाने मे किये अपराधो के लिए न्यूरेम्बर्ग का ट्रायल हुआ । आज जो भारतीय सविधान और कानून की सीमा थी उसके अन्दर श्रीमती इन्दिरा गाधी जैसे अपराधी को सजा नही दी जा सकती है । लेकिन हमारे नेतागण चाहते हैं कि सीमाओ के अन्दर ही सजा दी जाये । तो मैं अपने नेताओ से कहना चाहता हू — You cannot operate a carbuncle with a wooden knife

जब कानून की सीमाओ मे सजा देना है तो जहा तक कानून की सीमा हमे अलाऊ करती है वहा तक उनको सजा हमे देनी चाहिए, क्योकि सारा देश चाहता है कि इनको सजा मिलनी चाहिए । क्यो सजा मिलनी चाहिए ? क्योकि इन्दिरा जी ने ससदीय परम्पराओ की आत्मा की हत्या की है, वह इसलिए भी अपराधी हैं ? उन्होने देश की जबान बन्द की है, कलम तोड दी है, उन्होने न्यायपालिका की मर्यादा और अधिकारो को लूटना है । वह इसलिए भी अपराधी है कि उन्होने अपने परिवार की तानाशाही को देश पर कायम करना चाहती थी और उसके लिए उन्होने देश की जनता पर अत्याचार किये । इन सारे अपराधों के सम्बन्ध मे कानून मे कोई व्यवस्था नहीं है । उनका इनकन्सीवेबिल अपराध है । आज सारा राष्ट्र चाहता है कि इतने बडे अपराधी को सजा दी जाये । वह छूट गई तो उससे लोगो को खुशी नही हुई ।

SHRI VASANT SATHE (Akola) Let her be tried here We are willing to have her tried here Let us have it. If you have the courage, bring her Let us not argue on merits You prove it here

श्री मधु लिमये (बाका) माता जी से इन्स्ट्रक्शन्स पा कर आये है । माता जी ने कल पढाया है आपको, ऐसा लगता है ।

MR SPEAKER. Even if both the sides are agreed I may not agree, that is a different matter

SHRI VASANT SATHE The matter is before the House You have no choice It is only the House which can decide Rule 227 does not come in, if that is what you mean

MR SPEAKER I have to decide whether it is in order or not Therefore, I am hearing it

श्री गौरी शंकर राय मान्यवर, अगर यह प्रश्न केवल सदन के अपमान का होता

SHRI D B CHANDRE GOWDA (Chickmagalur) Is it for him to withdraw or wait for the Speaker's order?

SHRI MOHD SHAFI QURESHI (Anantnag) We have waited for three days How much time do you want? Why are you vacillating?

MR SPEAKER I am not vacillating. I will give a full hearing to you

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: You are giving an impression to us that you only listen when there is shouting.

MR SPEAKER This is also shouting.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: How many days will you take for giving a decision?

MR. SPEAKER: I will give a full hearing to this side also.

श्री गौरी शंकर राय अध्यक्ष महोदय, यह तकलीफ हमारे मित्र को नही होनी चाहिए। अगर यह केवल सदन के अपमान का प्रश्न होता तो निश्चित रूप से उनको सुनना चाहिए, सारी प्रक्रिया को जानना चाहिए।

मिसेज गांधी ने राष्ट्र का अपमान किया है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का अपमान किया है। एक अनयूजुअल क्रिमिनल से डील करने के लिए एक तेज हथियार की जरूरत थी, ऐसी मेरी मान्यता थी, लेकिन हमारे सदन के जो एल्डरली मेम्बर्स हैं।

मैं खत्म कर रहा हूं, देखिए, हूं कभी-कभी बर्दाश्त भी किया जाये।

मैं यह कह रहा था कि व्यक्तिगत रूप से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अच्छी संख्या में लोग इस बात में विश्वास करते है कि श्रीमती गांधी जैसे को सजा देने के लिए किसी पैराफर्नेलिया की जरूरत नही है, तुरन्त सजा देनी चाहिए। लेकिन हमारे सीनियर मेम्बर्स चाहते हैं कि उनको सुने। क्या उनको सुनेंगे? मगर हम उनको सुनने का अवसर देते हैं।

श्री वसन्त साठे : बता दो, हिम्मत है तो तुम्हारी मर्दानगी देख ले।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : कल तक तो बिल्ली के समान बैठे थे।

श्री गौरी शंकर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूगा। अपने मित्रों का दिल दुखाने वाली कोई बात नही कहूंगा। हमारे नेताओं ने तय किया है कि वह उनको सुनना चाहते है, क्योंकि उनकी जुबान बडी मीठी है। तो वह सुनें। इन बड़े नेताओं के आग्रह पर हमारे बड़े सीनियर मेम्बर्स ने मुझ से कहा कि यह उनका अधिकार था, हम एकसा व्यवहार करें। हम उन्हे सुनेंगे। हालांकि मैं उनकी कन्टैशन से इत्तिफाक नही करता हूं। For habitual criminals some unusual process must be adopted.

लेकिन मै वापिस लेता हूं अपने प्रस्ताव को इसलिए कि मेरे मित्रो का निवेदन है। I beg leave of the House to withdraw my amendment.

MR. SPEAKER: Has Mr. Rai the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI VASANT SATHE: No.

MR. SPEAKER: Those who are for withdrawal may please rise in their seats.

SEVERAL HON. MEMBERS rose

MR. SPEAKER: The leave is granted.

The amendment was by leave withdrawn

MR. SPEAKER: There are two more amendments. One is from Shri Roop Nath Singh Yadav and other is from Shri Vijay Kumar Malhotra. Are you moving?

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh): I beg to move:

That in the motion,—

For "a period of six months" *substitute* "the current session or by 21st of December, 1977 positively".

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi). I beg to move

That in the motion,—

For "within a period of six months" substitute "by Monday the 19th December 1977'

अध्यक्ष महोदय मुझे यह संशोधन पेश करना है। मधु लिमये जी की जो मोशन है उसमें 6 महीने का समय दिया है। मुझे यह मूव करना है कि इसका समय सोमवार, 19 दिसम्बर, 1977 तक रखा जाए। रिपोर्ट के लिए छ महीने का समय देने का मतलब यह होगा कि यह मामला अगले बजट सेशन में नहीं आयेगा, बल्कि उस के बाद होने वाले सितम्बर-अक्तूबर के सेशन म जायेगा। इस का परिणाम यह होगा कि तकरीबन एक साल और निकल जायेगा। इसमामले को हुए तीन चार साल पहले ही बीत चके हैं। इसलिए इसे एक और साल के लिए टालना बहुत ही गलत होगा।

माननीय सदस्य, श्री गौरी शकर राय, ने इस प्रश्न को इस सदन मे अभी तय करने के बारे मे जो बाते कही है, मैं उन मे से बहत सी बातो के साथ सहमत हू। मैं समझता हू कि अगर इस मामले को लम्बा लटकाया जायेगा, तो काग्रेस पार्टी यह कोशिश करेगी---उस की ये कोशिशें इस समय भी जारी हैं ---कि क्रिमिनल और इकानोमिक आफेंसिज को भी पोलीटिकलाइज कर के कण्ट्री को कनफ्यूज कर दिया जाये और इस कनफ्यूजन मे लोगो की दृष्टि मे उन क्राइम्ज और आफेंस की शक्ल बदल दी जाये।

मैं मानता हू कि अगर उन्हें एक साल और दे दिया गया, और अगर एक साल बाद उन्हें सजा भी दे दी गई, तो इस बीच म और बहुत से मामले हो जायेंगे, जिस से इस मामले की इम्पार्टेंस खत्म हो जायेगी। अभी एक महीना और बचता है। इस एक महीने मे उन्हें अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका दिया जा सकता है। उन्हे सुन लिया जाये, और उस के बाद प्रिविलिजिज कमेटी फैसला करे। चाहिए तो यह था कि इस हाउस मे ही इस प्रश्न क बारे म फैसला होता लेकिन ऐसा नही किया जा रहा है। लेकिन जब मिनिस्टर्ज और आफिसर्ज ने अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो बहुत ज्यादा मामला बाकी नही रहता है। फिर भी अगर उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना ही है, तो एक महीने का समय काफी है। यह सेशन 23 दिसम्बर तक चलेगा। अगर कमेटी की रिपोर्ट 19 दिसम्बर को आ जाये, तो हाउस को इस बारे म फैसला करने के लिए दो तीन दिन मिल जायेंगे। इसी लिए मै यह एमण्डमेंट मव करना चाहता हू।

MR SPEAKER Now, there has been a long discussion I first put the amendments to vote There is Mr Shyamnandan Mishra's amendment

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) I am not going to make a long speech. I am suggesting through my amendment that after the words 'Shrimati Indira Gandhi", the words "and others' be dropped My first reason is that the committal proceeding is essentially a judicial proceeding One must know clearly as to who are the persons involved in this The hon mover of the motion cannot say that the entire world is involved in this. We must know precisely who are the persons involved and we must come to a judgment about this in this House as to whether these persons are required to be committed to the Committee of Privileges Therefore, it is not precise and it is not definite

My other submission is that the person who has been the source of this crime is the person who must be pinned down The *mens rea*, the criminal

intent, cannot be put on the persons who have simply executed the order. The execution of order cannot be said to be an act, *prima facie*, which constitutes a breach of privilege because there was another person to give order for this.

For these two reasons, I would suggest to the hon. mover of the motion that he should accept my amendment that after the words "Shrimati Indira Gandhi", the words "and others" should be dropped. If he has got some persons in mind clearly and he thinks that he can establish a *prima facie* case against them, he should come before the House with those names.

MR. SPEAKER: Mr. Limaye, are you accepting the amendment of Mr. Shyamnandan Mishra?

श्री मधु लिमये: मुझे कुछ कहने दीजिए। जहां तक समय का सवाल है मैं अपने मित्र के सुझाव से सहमत नहीं हो सकता इसलिए कि यह जो अवधि है यह बहुत कम हो जायगी। आप जानते हैं कि प्रिविलेजेज कमेटी को कम समय दिया जाता है तो बार-बार वह सदन के सामने आते है। इसलिए अगर सदन की अनुमति हो तो एकाध महीना बढ़ा सकते है। बजट सेशन के अन्त में यह मामला आ सकता है। बजट मे तो दूसरा काम नहीं होता है। बजट पास होने के बाद जो सात आठ दिन बचते हैं उस मे यह आ सकता है। अगर सदन की रजामन्दी हो तो पांच महीने में करने के लिए तैयार हूं जिस में बजट के अन्त में यह आ जाय, बजट सेशन के लास्ट वीक में।

MR. SPEAKER: Even if you give six months, they can send a report earlier.

श्री मधु लिमये: दे सकते है तो जरूरत ही नहीं है बदलने की। विदिन की बात है तो कोई जरूरत नहीं है बदलने की।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): They can submit their report within six months.

श्री मधु लिमये: दूसरी बात—श्री श्याम नन्दन मिश्र जी का जो सुझाव है वह वैसे ठीक है, लेकिन नोटिस में जो मैंने कहा है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं और उसके बाद मैं क्यों असमर्थ हूं उसे स्वीकार करने में यह उन्हें पता चल जायगा।

मैंने नोटिस मे यह कहा है:

"My charge of contempt of the House is against the following persons:

(1) Mrs. Gandhi who directed raids against the officers for collecting information for Parliamentary Questions;

(2) Mr. Sen, the then Director of the CBI who conducted these raids on the basis of fabricated charge. If necessary, Mr. Bishan Tandon the then Joint Secretary in the PM's Secretariat and Mr. Shakdher the then Secretary-General, Lok Sabha, may also be asked to testify. If found involved, they should also be hauled up."

उस के ऊपर मैं ज्यादा कोई राय नहीं दे रहा हूं लेकिन सेन का नाम मैं नहीं छोड़ सकता हूं इसलिए 'ऐंड अदर्स" मैंने कहा है। आर्डर्स की बात क्या है? आर्डर्स का मतलब क्या यह है कि प्रधान मंत्री किसी को कहे कि तुम जा कर उस का मर्डर करो और वह मर्डर कर देगा, उस के बाद कहेगा कि आइ वाज अण्डर आर्डर्स? आर्डर भी कानून के दायरे के अन्दर होना चाहिए। इसलिए सेन साहब को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और नामों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऊपर 'ऐंड अदर्स" की जगह पर 'सेन' का नाम जुड़वा देंगे तो मैं मान लूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मुझे यह निवेदन करना है कि जब कमेटी आफ प्रिविलेजेज इस के ऊपर विचार करेगी और अन्य व्यक्तियों को भी अपराधी समझेगी तो उन को बुला सकता है। यह नहीं है कि आज अगर उन्होंने उन का नाम छोड़ दिया जिस का वह ले रहे हैं और कमेटी आफ प्रिविलेजेज की समझ में उन को इस के सिलसिले में लाना चाहिए तो वह उन को उस में ला नहीं सकती है, उन को भी कमेटी आफ प्रिविलेजेज लाएगी। उस के लिए इस में कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मधु लिमये : तो ठीक है, सेन को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो ऐड मिस्टर सेन कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) मैं ने भी एक नोटिस दिया था और एक मधु लिमये जी ने दिया था। मैंने अपने नोटिस में तीन नाम दिए हैं —एक सेन का, एक इंदिरा जी का और तीसरा धवन का। तो वह दोनों नोटिस जाएंगे प्रिविलेजेज कमेटी के सामने, इन का भी जायेगा और हमारा भी जायगा ... (व्यवधान)

MR SPEAKER: You have not moved them You have agreed

SHRI KANWAR LAL GUPTA: But my notices will go to the Committee of Privileges

MR SPEAKER: That will go.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: That will go to the Committee of Privileges, in any case

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): The privilege motion moved by Mr. Madhu Limaye has already been referred to the Committee of Privileges.

MR. SPEAKER. It has not been referred.

SHRI HARIKESH BAHADUR: The privilege motion which has already been moved by Mr. Kanwar Lal Gupta should also be referred to the Committee of Privileges because in that motion there is a reference to breach of privilege against some more persons besides Mrs Indira Gandhi.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Both will be referred to the Committee of Privileges The names mentioned by me and Mr Madhu Limaye should be considered by the Committee of Privileges and not beyond that That is my contention So, whatever the resolution may be, it should govern all the names mentioned in the notice

MR SPEAKER There has been enough of discussion There is an amendment moved by Shri Nirmal Chandra Jain He is not here today All the same, he has moved his amendment and it is in the possession of the House Therefore, I will first put his amendment to the vote of the House His amendment is After 'Shrimati Indira Gandhi' insert 'Shri R K Dhawan and Shri D Sen' Is it the pleasure of the House to accept the amendment moved by Mr. Jain? I suppose the House does not support it Then I go to the amendment moved by

SOME HON MEMBERS: You put it to the vote of the House

MR SPEAKER: Now I put the amendment moved by Shri Nirmal Chandra Jain to the vote of the House The amendment was put and negatived

MR SPEAKER: We go to the other amendment moved by Shri Shyamnandan Mishra that is, delete the words "and others".

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is for the Chair to decide whether the motion is in form—as is capable of a judicial determination by the Committee.

MR. SPEAKER: The fact that I have given the consent means that it is in form.

Now, I put Shri Shyamnandan Mishra's amendment to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR SPEAKER: Now I come to the amendment moved by Shri Roop Nath Singh Yadava. ..

SHRI ROOP NATH SINGH YADAVA: I want to withdraw my amendment. I seek leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR SPEAKER. Now I come to Shri Vijay Kumar Malhotra's amendment

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: I also want to withdraw my amendment I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn

MR. SPEAKER Now I come to the main motion.

The question is:

"That the question of breach of privilege and contempt of the House against Shrimati Indira Gandhi and others be referred to the Committee of Privileges with instructions to report within a period of six months."

Those in favour will please say 'Aye'.

SEVERAL HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. SPEAKER: Those against will please say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: 'No'.

MR. SPEAKER: The 'Ayes' have it, the 'Ayes' have it, the 'Ayes' have it. The motion is adopted. (*Interruptions*). Are you pressing for a Division? (*Interruptions*) I think Mr. Sathe is challenging it. Now, those in favour will please rise in their seats....

SEVERAL HON. MEMBERS: *rose*—

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): On a point of order, Sir. Please do not make the Members of Parliament behave like school boys. Every time you are asking them to stand up....

MR. SPEAKER: When a voice vote was taken, I think, Mr. Sathe challenged it....

AN HON. MEMBER: No. He has not challenged. Why do you make us stand up like school boys? (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: I do not want a Division. There are only two alternatives in this House: (a) Voice Vote, and (b) Division. Now, you are introducing a third one, namely, making them stand up. Next time you will, perhaps, ask them to stand up on their benches.

SHRI SAUGATA ROY: They are the ruling Party, Sir. Please do not make them stand up.

MR. SPEAKER: The motion is adopted.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): You have not asked those who are against to get up.

MR. SPEAKER: They say that the voice vote is all right.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Sir, you asked us, namely, those who are in favour of the motion, to stand up; and we stood up. Now you should ask those against to stand up.

MR. SPEAKER: They have withdrawn their objection. I declare, that the motion is adopted.

The motion was adopted.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am on a point of procedure. The Chair put Mr. Madhu Limaye's motion to vote by a voice vote but because just one Opposition Member said that he challenges it, you, Sir, asked those Members supporting the motion to stand. (*Interruptions*). We stood up. Now, therefore those against the motion should also be asked to stand up.

MR. SPEAKER. I have already declared the result and it is no more open to discussion. I have declared that the motion is carried.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : मेरा एक प्वाइण्ट आफ आर्डर है कि क्या इस सदन में किसी को खड़ा होने के लिए बाध्य किया जा सकता है ? ये लोग बैठे रह गये ।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Sir, I am on a point of order. I draw your attention to Rule 197. Yesterday I gave notice of a Calling Attention motion for the....***

MR. SPEAKER: There is no point of order involved. This is not going on record because you have not taken my permission. Nothing about that will go on record.

13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

GROUNDUT OIL (REGULATION OF REFINING AND PRICE) CONTROL ORDER, 1977

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): I beg to lay on the Table a copy of the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control Order, 1977, published in Notification No. S.O. 602(E) in Gazette of India dated the 1st August, 1977, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-1091/77].

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. No. 492 DATED 15-7-77 RE. EXTENSION OF JAMMU AIRPORT

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): I beg to lay on the Table a statement correcting the answer given on the 15th July, 1977 to a supplementary question by Shri Mohd. Shafi Qureshi on Starred Question No. 492 by Dr. Karan Singh regarding extension of Jammu Airport.

Statement

In the reply to the supplementary question by Shri Mohammed Shafi Qureshi, on the Starred Question No. 492 given in the Lok Sabha on the 15th July, 1977, it has been stated:

"That route is still under investigation. The loss on the Delhi-Jammu route is estimated at Rs. 27 lakh and 23 thousand. If this route is operated with Boeing the loss will increase to Rs. 1 crores 65 lakh and 45 thousand. Under such circumstances I do not think that the scheme can be taken up immediately".

It has since been found that this position is not wholly correct in so far as the figures of loss are concerned. The correct reply is as under:

"That route is still under investigation. The loss by operating HS-748 aircraft through Jammu was estimated in July, 1974 at Rs. 37.23 lakhs per annum. If a Boeing is operated through Jammu the loss is estimated at Rs. 1,62,45,000/-.

*** Not recorded